

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-...28/...7/2025.

**** अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित।**

द्वारा :-

****वित्त विभाग।**

विषय :-

राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक तीन वर्षों में कुल ₹ 2850.00 लाख (रुपये अठाईस करोड़ पचास लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्पेड, पटना के मुख्यालय में एक केन्द्रीकृत इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एवं कमाण्ड सेन्टर की स्थापना एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 1639.00 लाख (रुपये सोलह करोड़ उनचालीस लाख) मात्र सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के रूप में व्यय करने की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक तीन वर्षों में कुल ₹ 2850.00 लाख (रुपये अठाईस करोड़ पचास लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्पेड, पटना के मुख्यालय में एक केन्द्रीकृत इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एवं कमाण्ड सेन्टर की स्थापना एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 1639.00 लाख (रुपये सोलह करोड़ उनचालीस लाख) मात्र सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के रूप में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. कॉम्पेड मुख्यालय में लगभग 4000 वर्गफीट क्षेत्र में एक केन्द्रीकृत कमाण्ड एवं कन्ट्रोल केन्द्र की स्थापना की जाएगी, सभी डेयरियों, बल्क मिल्क कूलरों, शीतकरण केन्द्रों एवं समितियों से 24 घन्टे जुड़ा रहेगा, जिससे विभिन्न स्त्रोतों से आँकड़े एवं विडियो फीड उपलब्ध हो सकेगा। इस केन्द्र द्वारा ही आवश्यकतानुसार आई०ओ०टी० उपकरणों की स्थापना, डेयरी की सभी डेयरीयों, तथा दूध परिवहन के टैंकरों तथा वितरकों की गाड़ियों में जी०पी०एस० सिस्टम की स्थापना तथा दूध की गाड़ियों में तापक्रम हेतु डाटा लॉगर की स्थापना तथा उससे समन्वय रखा जाएगा। इन सभी आंकड़ों को डाटाबेस में संरक्षित करने के अतिरिक्त बड़े विडियो मॉनिटर पर भी देखा

जाता रहेगा। इसमें स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाईयों से प्राप्त आंकड़े में प्रदर्शित होंगे एवं पर्यवेक्षण हेतु निर्बाध रूप से कर्मी उपस्थित रहेंगे। एकीकृत कमान्ड और कन्ट्रोल सेन्टर (ICCC) परियोजना को स्थापित करने में वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक तीन वर्षों में कुल ₹ 2850.00 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹ 1639.00 लाख अनुमानित व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

3. कॉम्पेड मुख्यालय में इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एवं कन्ट्रोल केन्द्र की स्थापना की जायेगी, जिसमें निहित प्रणालीयाँ निम्न रूपेण होंगे :-

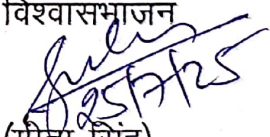
- (i) डाटा मॉनिटरिंग की सुविधा :- कॉम्पेड के अन्तर्गत विभिन्न संघ/इकाई से संबंधित सभी डाटा की एकीकृत निगरानी की व्यवस्था होगी, जिससे की विभिन्न परिचालन प्रक्रियाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी। इसमें वास्तविक समय (Real Time) में डाटा की समीक्षा एवं विश्लेषण सम्भव होगा जो की निर्णय प्रक्रिया तेज और सटीक बनाने एवं उत्पादन, संग्रहण, वितरण और वित्तीय लेन-देन का बेहतर प्रबंधन में सहायक होगा जिससे किसानों द्वारा आपूर्तित दुग्ध का उचित भुगतान सुनिश्चित मॉनिटरिंग की सुविधा।
- (ii) टैंकर जी०पी०एस० मॉनिटरिंग प्रणाली :- जी०पी०एस० प्रणाली से दूध और संबंधित उत्पादों के टैंकरों की आवाजाही की सटीक निगरानी होगी, जिससे की रूट मैपिंग और समय प्रबंधन में सुधार किया जा सकेगा। इस प्रणाली के समावेश से किसी भी प्रकार की अनियमितता की त्वरित पहचान एवं समाधान सम्भव होगा साथ ही परिवहन के दौरान दूध एवं दुग्धजन्य उत्पाद की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- (iii) सी०सी० टीवी निगरानी प्रणाली :- इस प्रणाली से संघ/इकाई के परिसरों की 24 x 7 निगरानी सम्भव होगी और चोरी, दुर्घटना या किसी भी अप्रत्याशित घटना का त्वरित पता लगाया जा सकेगा जिससे की सुरक्षा मानकों में सुधार कर परिसरों को सुरक्षित बनाया जा सकेगा।
- (iv) Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली :- कॉम्पेड द्वारा किसानों एवं लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान के उद्देश्य से Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली अपनायी जा रही है। इस परिपेक्ष्य में डी०बी०टी० को भी एकीकृत कमान्ड और कन्ट्रोल सेन्टर (ICCC) से एकीकृत किया जाएगा जिससे की किसानों को उनके दूध के मूल्य सीधे उनके खातों में ससमय भुगतान सम्भव होगा एवं किसानों को समय पर उनका लाभ प्राप्त होगा तथा लाभार्थियों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सकेगा।

4. मुख्य शीर्ष-2404 -डैरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 -डैरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या-02, उप शीर्ष-0115 -गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02-2404001020115, विषय शीर्ष-0115.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा।

5. दिनांक-25.04.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है (पृष्ठ 09-08/प०)।

6. चूँकि यह योजना एक नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 15.00 करोड़ से अधिक एवं 30.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प-12888, दिनांक-03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०-6 एस०एस०(6)22/2025 के पृष्ठ-09/टि०, दिनांक-14.05.2025 एवं पृष्ठ-31/टि०, दिनांक-21.07.2025.
7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०-6 एस०एस०(6)22/2025 के पृष्ठ-08/टि० तथा डायरी सं०-204, दिनांक-30.04.2025.
8. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/ 2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
9. संबंधित स्वीकृत्यादेश अंतर्गत 18 माह पूर्व निकासी किये गये राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से अगले तीन माह के अंदर कराना सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी एवं व्यय समय-समय पर वित्त विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।
11. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

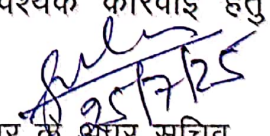
विश्वासभाजन


(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक:-6 एस०एस०(6)22/2025- /पटना-15, दिनांक-...../...../2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)22/2025-3380/पटना-15, दिनांक-28/7/2025.
प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार प्रदाधिकारी, सचिवालय
कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)22/2025-3380/पटना-15, दिनांक-28/7/2025.
प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड,
पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)22/2025-3380/पटना-15, दिनांक-28/7/2025.
प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/
योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)22/2025-3380/पटना-15, दिनांक-28/7/2025.
प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना
शाखा-06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)22/2025-3380/पटना-15, दिनांक-28/7/2025.
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/
विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा,
महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)22/2025-3380/पटना-15, दिनांक-28/7/2025.
प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर
कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

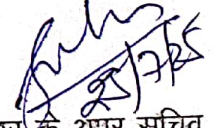
राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक तीन वर्षों में कुल ₹ 2850.00 लाख (रुपये अठाईस करोड़ पचास लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर कॉम्पेड, पटना के मुख्यालय में एक केन्द्रीकृत इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एवं कमाण्ड सेन्टर की स्थापना एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 1639.00 लाख (रुपये सोलह करोड़ उनचालीस लाख) मात्र सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के रूप में व्यय करने की स्वीकृति हेतु व्यय विवरणी :-

(राशि लाख में)

विषय शीर्ष	योजना का विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28	कुल योग	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
विपत्र कोड 02- 2404001020115, विषय शीर्ष-0115.31.05 -सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद	इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल एवं कमाण्ड सेन्टर	1639.00	711.00	500.00	2850.00	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
योग		1639.00	711.00	500.00	2850.00		

(रुपये अठाईस करोड़ पचास लाख) मात्र

3380
28/7/25


 सरकार के अपर सचिव